

कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो : सुदेश

नवीन मेल संवाददाता। सिल्ली प्रखण्ड कार्यालय समीप सोनाली लॉज में झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में प्रखण्ड स्तरीय 'रुआर स्कूल' 2023 कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि विधायक सुदेश कुमार महतों व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ञवित कर किया। विधायक सुदेश कुमार महतों ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए रुआर स्कूल अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर वैसे बच्चों के विद्यालय वापसी कराया जाता है जो कार्यशाला में 22 जून से 15



इसके लिए तभी मिलकर प्रयास करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश 06 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों का भ्रमण कर स्कूल के छोटे से दूर रहे 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को पुनः स्कूल तक लाने के मकान से बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में

जुलाई तक चलने वाला कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधि, प्रबंधन समिति के पदाधिकारी सहित तथा स्कूल के शिक्षक पोषक क्षेत्र का भ्रमण कर प्रसार पदाधिकारी विमल कांठ ज्ञान के प्रयोग के खाली सामाजिक तथा आपसी सहायता के सामाजिक तथा आपसी सहायता के लिए विद्यालय से डॉकर उसका ठहराव सुनिश्चित करना कराया जाता है जो कार्यशाला में 22 जून से 15

तिथिवार कार्यक्रमों के निष्पादन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संचालन वां पी औं मनोज कुमार और धर्मवाल धर्मवाल जापन प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी विमल कांठ ज्ञान के प्रयोग के खाली सामाजिक तथा आपसी सहायता के सामाजिक तथा आपसी सहायता के लिए विद्यालय से डॉकर उसका ठहराव सुनिश्चित करना कराया जाता है जो कार्यशाला में 22 जून से 15

लापुंग प्रखण्ड में चार दिनों से दर्जनों घरों की बिजली हुई ठप

जीवन रक्षक दवाइयां होने लगी हैं खराब : गंगाधर

नवीन मेल संवाददाता। लापुंग लापुंग प्रखण्ड के कक्रिया, डाईआर मलागो, महांगव सहित कई पंचायतों के दर्जनों गांवों में पिछले चार दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप रहने के कारण जनजीवन अत वस्त नहीं गया है। बिजली के अधाव में गांव के ग्रामीण विधिक सेवा से संबंधित योजना का लाभ अवश्य ठाउं। साथ ही उहोने प्रखण्ड में चल रहे विधिक और कर्मी कार्यकारी योजनाएं की जानकारी दी है। उहोने कहा कि राज्य विधिक सेवा के कर्मियों के अनुसार कमडारा से लापुंग लेना ही नहीं जानकारी भी रखना बहुत महत्वपूर्ण है सिंगों सुमंत तिकी ने लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने आहान करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख योजनाओं सहित अत योजनाओं के बारे में उपरित लोगों को जानकारी दी। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए जाने वाले कानूनी सेवाओं के बारे में बतलाया।



विद्युत विभाग के कर्मियों के अनुसार कमडारा से लापुंग करकरिया तक विद्युत ट्रांसफारेशन लाइन में फॉल्ट आ गई है लेकिन लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने आहान करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख योजनाओं सहित अत योजनाओं के बारे में उपरित लोगों को जानकारी दी। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए जाने वाले कानूनी सेवाओं के बारे में बतलाया।

उहोने कहा कि सिंग योजनाएं

कलश यात्रा के साथ पांच दिवसीय महायज्ञ शुरू

ऐसे आयोजन से भक्ति की भावना का प्रसार होता है : सुनीता चौधरी



नवीन मेल संवाददाता
रामगढ़। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र
के रामगढ़ नगर परिषद के
अंतर्गत छत्तर मांडू में श्री श्री राधा
कृष्ण मन्दिर जीणोंद्वार मूर्ति प्राण
प्रतिष्ठा एवं पांच दिवसीय महायज्ञ
को तहत 24 जून को कलश यात्रा
का आयोजन किया गया। जिसमें
मुख्य अर्तिथ रामगढ़ विधानसभा

की विधायक सुनीता चौधरी, विशिष्ट अतिथि रामगढ़ नगर परिषद उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो शामिल हुए, मौके पर सुनीता चौधरी ने कहा की क्षेत्रवासियों के सफल सुखद एवं स्वास्थ्य जीवन सुख समृद्धि की कामना करते हैं, कहा इस तरह के आयोजन से भक्तिमय का

वातावरण बनता है .मैंके पर
धनेश्वर महतो, किशुन राम मुंडा,
कमिटी के अध्यक्ष भवानी महतो,
सचिव सच्चीनंद महतो, उपाध्यक्ष
ईश्वर प्रसाद, कोषाध्यक्ष प्रदीप
कुशवाहा, संरक्षक रामनरेश
महतो, सुनील कुमार, सुभाष
महतो, शंकर प्रसाद महतो, नरेश
साहू, बासुदेव महतो, दिनेश

कुमार, संजय कुमार, कृष्ण
 प्रसाद, दिनेश कुमार, पवन कुमार,
 संतोष कुमार, कर्जरू महतो,
 विवेक प्रसाद कुशवाहा, दीपक
 कुमार, रुपेश कुमार, नटवरलाल
 कुशवाहा, संतोष सोनी, देवनंव
 कुमार, गणेश कुशवाहा, अनूप
 यादव, दिलीप यादव सहित अन्य
 मौजूद थे।

धूमधाम से निकाली गयी साईं बाबा की पालकी यात्रा



नवीन मेल संवाददाता
रामगढ़। शहर के राधा कृष्ण
कॉलोनी स्थित आनंद साई दरबार
13 वां तीन दिवसीय स्थापना दिवस
समारोह साई बाबा की पालकी
यात्रा के साथ 24 जून को आरंभ
हुआ। पालकी यात्रा से पूर्व पुजारी
द्वारा साई बाबा की विधिवत पूजा
अर्चना की गई। उसके पश्चात मंदिर
परिसर से गाजे बाजे के साथ साई
बाबा की पालकी यात्रा आरंभ हुई।
पालकी यात्रा झंडा चौक, चट्टी
बाजार, लोहार टोला, सुभाष चौक,
मेन रोड होते हुए वापस मंदिर
परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
पालकी यात्रा के दौरान श्रद्धालु साई
बाबा के मधुर भजन गाते बढ़ते
चल रहे थे। जिससे शहर का
वातावरण भक्तिमय हो गया था।
साई बाबा की पालकी यात्रा का
शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत
किया गया। वहीं, पालकी यात्रा के
गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर गुरुद्वारा
प्रबंधक कमेटी की ओर से पालकी
यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का
शीतल पेयजल के साथ स्वागत
किया गया। आनंद साई दरबार से
आयोजित साई बाबा की पालकी
यात्रा के दौरान साई बाबा का वेष
धारण किये पूर्व विधायक जयुमा
शर्मा के पुत्र विमल शर्मा लोगों के
बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे।

वर्हीं, आनंद साई दरबार के 13वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर मंदिर का रंग रोगण कराया गया है। साथ ही मंदिर की आकर्षक विद्युत बल्बों से सजावट की गई है। जिससे मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। स्थापना दिवस समारोह के तहत दूसरे दिन 25 जून को मंदिर में विशेष पूजन का आयोजन किया जाएगा। जबकि 26 जून को अटूट भंडारे के साथ स्थापना दिवस समारोह का समापन होगा। साई बाबा की पालकी यात्रा में झारखंड सेवा समिति के अध्यक्ष अमित सिन्हा, झारखंड वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर गुप्ता उर्फ नंदु बाबू, अजीत जायसवाल, प्रो संजय सिंह, संतोष सिन्हा, विजय मेवाड़, जितेंद्र प्रसाद डल्लू, मुन्ना सिन्हा, राजेश साव, विनोद साव, अरविंद अग्रवाल, जीतू अग्रवाल, आनंद सिन्हा, संजय दांगी, बादल, सनी सिन्हा, आनंद सिंह, उत्तम, नवनीत कुमार, मनोज मंडल, अजय कुमार, बसंत कुमार, कैलाश चंद्र साह, आयुष कुमार गुप्ता, सुरेश प्रसाद, मौजन कुमार, सलमान, अशोक कुमार महतो, अनूप विश्वकर्मा, दीपक सहित अनेक अद्भुत शामिल हुए।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर चलाया कुष्ठ रोगी

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दिनांक 15/06/2023 से 28/06/2023 तक कुष्ठ रोग खोजी अभियान चलाया जाना है। जिसके लिए रामगढ़ जिले के 1215 टोला को चिन्हित कर 201 सुपरवाइजर एवं 1157 सहियाओं के साथ 1157 टीम बनाये गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ सविता वर्मा और उनकी टीम द्वारा चितरपुर, कोठार एवं मुरामकला में कुष्ठ रोगी खोजो अभियान चलाया गया। साथ ही मौके पर डॉ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में कुष्ठ रोग को लेकर फैले भ्रातियों को दूर करना है।

A photograph showing a woman with short dark hair, wearing a pink patterned dress, gesturing with her hands as she speaks to a man. The man, wearing a dark blue shirt and glasses, holds a green folder or book and looks towards her. They appear to be in an indoor setting with other people visible in the background.

नवीन मेल संवाददाता
बरही । करियातपुर के ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी के नाम आवेदन देकर भीम आर्मी के कुछ सदस्यों पर शार्ति सौहार्द बिंगाड़ने का आरोप लगाया गया है. दिए आवेदन में बताया गया कि भीम आर्मी सेना के लक्ष्मण रविदास, राहुल कुमार, सुनील रविदास, जितेंद्र रविदास, अनिल रविदास, हेमंत रविदास और पारस शरण देव ने करियातपुर दुर्गा के बगल के मैदान में बाबा साहब का स्मारक बनाया जा रहा है. 21 जून को इन लोगों की अगुवाई में उक्त स्थल पर स्मारक के शिलान्यास किया कर्ता सौहार्द बिंगाड़ने का काम किया गया है. आरोप लगाया गया कि उक्त स्थल सामाजिक तंत्रिका है जिस पर

आरोप

दो पक्ष आमने-सामने, मासला पहुंचा थाना व अंचल

स्थल जांच की दिए गए है आदेश। उचित कारबाई होगी : सीओ



दुर्गा पूजा एवं अन्य कार्यक्रमों में
मिला इत्यादि का आयोजन किया
जाता है। ऐसे में भविष्य में होने वाले
भीड़ भाड़ में बाबा साहब की
स्थिति हो सकती है।

ए है आदेश। उचित कारबाई होगी : सीओ और जिला

और जिला परिषद सदस्य को भी दिया गया है। क्या कहते हैं मुखिया: स्थानीय मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि मामला सरकारी जमीन से संबंधित है इसकी सूचना अंचलाधिकारी को ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। सीओ से नियम संगत कार्रवाई करने की अपील की जाती है।

क्या कहते हैं सीओ : मामले के संबंध में सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो ने बताया कि मामला सरकारी जमीन की है. ऐसे में किसी भी संरचना के लिए अनुमति आवश्यक होते हैं. बाबा साहब का स्मारक बनाना अच्छी बात है परंतु बिना अनुमति की सरकारी जमीन का अतिक्रमण अनुचित है. जांच जांच नहीं कर्ता नहीं है तभी नहीं

ए है आदेश। उचित कारबाई होगी : सीओ और जिला

और जिला परिषद सदस्य को भी दिया गया है, क्या कहते हैं मुखिया: स्थानीय मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि मामला सरकारी जमीन से संबंधित है इसकी सूचना अंचलाधिकारी को ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। सीओ से नियम संगत कार्रवाई करने की अपील की जाती है।

क्या कहते हैं सीओ : मामले के संबंध में सीओ अरविंद देवाशीष टोणे ने बताया कि मामला सरकारी जमीन की है। ऐसे में किसी भी संरचना के लिए अनुमति आवश्यक होते हैं। बाबा साहब का स्मारक बनाना अच्छी बात है परन्तु बिना अनुमति की सरकारी जमीन का अतिक्रमण अनुचित है। जाच जांच करने की वार्ता भी जारी

एक नजद इधर गी

भारत के समृद्धशालियों व प्रतिभाओं का पलायन क्यों?

धनाद्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। ऐसे क्या कारण है कि लोगों को देश की बजाय विदेश की धरती रहने, जीने, व्यापार करने, शिक्षा एवं रोजगार के लिये अधिक सुविधाजनक लगती है, नये बनते भारत के लिये यह चिन्तन-मंथन का कारण बनना चाहिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित 6,500 हाई- नेट-वर्थ ईंडिविजुअल्स (एचएनआई) के 2023 में भारत से बाहर जाने की संभावना है, पिछले वर्ष की तुलना में यह करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च निवल मूल्य वाली व्यक्तिगत आबादी के 2031 तक 80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है, जो इस अवधि के दौरान भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते धन बाजारों में से एक के रूप में स्थापित करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देश के भीतर संपन्न वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी। इसमें समृद्ध व्यक्तियों के भारत लौटने की प्रवृत्ति को भी देखा जा रहा है, और जैसे-जैसे जीवन स्तर में सुधार जारी है, यह अधिक संख्या में धनवान व्यक्तियों के भारत वापस आने का अनुमान लगाता है। लेकिन प्रश्न है कि भारत के करोड़पति आखिर नये बनते भारत एवं उसकी चिकित्सा, शिक्षा, अर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक उज्ज्वलता के बावजूद क्यों विदेश जा रहे हैं? वैसे तो यह हर किसी का व्यक्तिगत अधिकार और जाहत हो सकती है कि वह कहां बसना और कैसी जीवनशैली चाहता है? लेकिन हाई नेटवर्थ वाले (अति समृद्ध) हमारे देशवासियों के देश छोड़ कर कहीं और बसने की तैयारी की ताजा रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है।

दुनियाभर में धन और निवेश प्रवासन के रुझान को टैक करने वाली कंपनी की सालाना रिपोर्ट में अति समृद्ध भारतीयों का अपना सब-कुछ समेट कर हमेशा के लिए भारत से जुदा हो जाने का अनुपान अनेक प्रश्न खड़े करता है, सरकार को इन प्रश्नों पर गैर करने की ज़रूरत है। संतोष इस बात पर किया जा सकता है कि ऐसा कदम उठाने वाले इन अति समृद्धशालियों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग एक हजार कम है। लेकिन यह संख्या समूचे विश्व में सर्वाधिक है। भारत के दृष्टिकोण से इस तथ्य का विश्लेषण ज्यादा ज़रूरी हो जाता है। जानना यह भी ज़रूरी है कि बचपन से जवानी तक का एक-एक पल देश में गुजारने और यहीं अमीर बनने का सफर तय करने के बाद देश से मोह भंग होने के कारण आखिर क्या हो सकते हैं? उमीद यह की जाती है कि देश में रहकर समृद्ध हासिल करने वाले समय अनेक देश को लौटाएंगे भी। सवाल यही है कि देश को लौटाने और फायदा देने का वक्त आता है तब एकाएक विदेश में जाकर बसने की ललक कैसे और क्यों पैदा हो रही है? अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के समय इस तरह की पलायनवादी सोच का उभरना व्यक्तिगत स्वार्थ, सुविधा एवं संकीर्णता को दर्शाता है। बड़ा सवाल यह भी उठाना स्वाभाविक है कि आखिर क्या कमी है हमारे यहां? यह बात सही है कि गांव से कस्बे, कस्बे से शहर और शहरों से महानगरों में जाकर बसने की मानवीय प्रवृत्ति होती है। इसे विकास से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब यह दौड़ बहुत ज्यादा होने लगे और लोग अपनी जड़ें ही छोड़ने को आकुल दिखें तो सोचना ज़रूरी हो जाता है। मुर्खई, दिल्ली, बैंगलूरु जैसे महानगर दुनिया के दूसरे महानगरों को टक्कर देने वाले हैं। फिर भी अगर ये भारतीय विदेशी महानगरों को ही चुन रहे हैं, तो तमाम पहलुओं पर विचार भी करना होगा। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि यह दौड़ भारतीय महानगरों से विदेशी महानगरों की तरफ ही है।

■ ललित गर्ग

बराक ओबामा भारत को सुरक्षा की सीख न दें

देखा जाये तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस साक्षात्कार की टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठे ही हैं साथ ही इसके जरिये वह टूलिकिट भी सामने आ गयी है जिसके जरिये मोदी को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को लेकर निशाने पर लेने का प्रयास किया जाता है। अमेरिकी के राजकीय दौरे पर गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जब राष्ट्रपति जो बाइडन तथा उनका पूरा प्रशासन पलक पांचवड़े बिछा रहा था उसी समय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीएनएन को दिये एक साक्षात्कार के जरिये सनसनी फैलाई दी। इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत के मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई। साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करता तो मैं उनसे कहता कि अगर वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो भारत के टूटने की संभावना बनी रहेगी। ओबामा ने राष्ट्रपति जो बाइडन को भी सलाह दी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करें। देखा जाये तो ओबामा के इस साक्षात्कार की टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठे ही हैं साथ ही इसके जरिये वह टूलिकिट भी सामने आ गयी है जिसके जरिये मोदी को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को लेकर निशाने पर लेने का प्रयास किया जाता है। विदेशी मीडिया का इस संबंध में खूब सहारा लिया जाता है। बीबीसी गुजरात दंगों के 20 साल बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जनरल की पत्रकार सबरीना सिंहीकी को भारत में हो रहे विकास या मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछने की बजाय सिर्फ अल्पसंख्यकों की चिंता सताती है। आप जरा सभी घटनाओं को जोड़ कर देखेंगे तो आपको सारी कड़ियां जुड़ी हुई नजर आयेंगी। भारतीय प्रधानमंत्री की धेराबंदी करने के लिए धर्म का धंधा करने वाले टूलिकिट से जुड़े लोगों ने मोदी के अमेरिका आगमन से पहले कुछ भारत विरोधी अमेरिका संसदों से एक पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखवाया और उनसे मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। भारत विरोधी कुछ अमेरिकी संसद ने मोदी के स्वागत समारोह और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के संबोधन का बहिष्कार भी किया। यह लोग मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रैवीट और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट भी करते रहे ताकि मोदी विरोधी अभियान को गति मिलती रहे। इसके अलावा, एक ओर उमर खालिद को रिहा करने की मांग संबंधी पोस्टर अमेरिका में लहराये गये तो दूसरी ओर खालिस्तान समर्थकों ने भी भारत विरोधी नारे लगाये। इस बीच, सबके सुर से सुर मिलाते हुए बराक ओबामा ने सीएनएन को साक्षात्कार देकर माहील गमार्ने का प्रयास कर अपना भी योगदान दे दिया। देखा जाये तो बराक हुसैन ओबामा के मन में मोदी विरोधी भावना आज से नहीं बल्कि शुरू से ही है। ओबामा को 2014 में यह कर्तव्य नहीं भाया कि आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के इनी प्रचंड विजय हुई कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से सीधे मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गये। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबामा प्रशासन इस बात के लिए मजबूर हो गये।

स्वामी, पारिजात माइनिंग इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. की ओर से 502, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखण्ड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/1555
नंबर : 06562-241176 / 231257, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल, मंगलमूर्ति हाईट्स, र

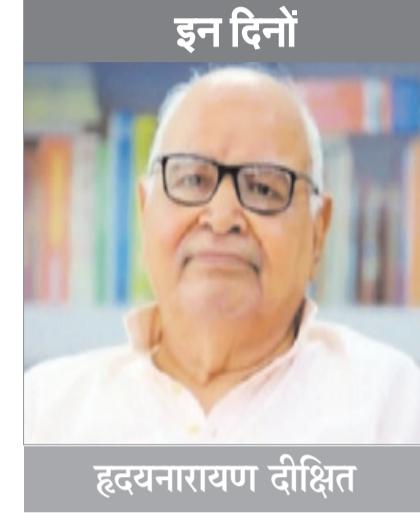
आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह ग्रासदी

भारत में संविधान का शासन है संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में खुबसूरत अधिकार विभाजन किये हैं लेकिन आपातकाल आधुनिक इतिहास में संविधान को तहस-नहस करने की भयावह त्रासदी है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज से 48 वर्ष पूर्व (25 जून 1975) पूरे देश को कैदखान बना दिया था। संविधान (अनुच्छेद 352) में वाद्य आक्रमणों और देश के भीतर गंभीर आतंरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित करने की व्यवस्था थी। लेकिन तब देश में कोई आतंरिक अशांति नहीं थी प्रधानमंत्री स्वयं आतंरिक अशांति से पीड़ित थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को उनका संसदीय चुनाव अवैध घोषित कर दिया था न्यायालय के अनुसार वे अनुचित साधनों द्वारा चुनाव जीती थीं रायबरेली (उत्तर प्रदेश) की उनकी संसदीय सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। सत्ता पक्ष का एक धड़ा और संपूर्ण विपक्ष त्यागपत्र मांग रहा था। उन्होंने पद से न हटने का निश्चय किया आपातकालीन प्राविधान का दुरुप्योग किया और आपातकाल थोप दिया संविधान के रास्ते तानाशाही थोपने के ऐसा ही कृत्य एडोल्फ हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को जर्मनी में किया था हिटलर जर्मनी के चांसलर (सत्त

प्रमुख) थे। आपातकाल पर जर्मनी की संसद में मतदान हुआ। संसद का बहुमत हिटलर के पक्ष में था। 444 मत आपातकाल के पक्ष में पड़े। विपक्ष में 94 वोट पड़े। 109 लोगों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह भारत में भी सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री के पक्ष में था। जान पड़ता है कि श्रीमती गांधी हिटलर से प्रेरित थीं। यहां पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था। जर्मनी की तर्ज पर यहां कांग्रेस संसदीय दल और पार्टी ने इस तानाशाही का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा को इंडिया बताया और इंडिया को इंदिरा। स्वाधीनता आंदोलन के महान नेता जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सहित सभी राष्ट्रवादी नेता भी जेल में थे। मानवता कुचली गई। पुलिस अंग्रेजी शासन की पुलिस की भूमिका में थी। विचार अधिक्यक्ति का गला घोट दिया गया। प्रतिष्ठित पत्रकार पीड़ित किये गये। प्रधानमंत्री न्यायालयों की शक्ति पर आक्रामक थीं। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की। संविधान में हास्यास्पद संशोधन हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को न्यायालयिक निर्वचन से मुक्त कराने का संशोधन कराया गया और इस संविधान संशोधन को पिछली तारीखों से लागू कराया गया। आपातकाल के बयालिसवां संशोधन ध्यान देने योग्य है। संविधान में संसदीय अधिनियम पर भी न्यायालयिक पुनर्निर्लोकन की व्यवस्था है। लेकिन आपातकाल में संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने के लिए संघ और राज्यों के कानूनों में भेद किया गया। यह

तत्वों को लागू करने के लिए अधिनियमित कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी। इसी तरह उच्च न्यायालयों को केन्द्रीय विधि की असंवैधानिकता के विरुद्ध सुनवाई से रोक दिया गया। किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायमूर्तियों के विशेष है। आपातकाल में संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 का भी संशोधन किया गया। व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन विधि के नाम से घोषित विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अकारण जेल भेजा गया। लाखों कार्यकर्ता जेल

(मीसा) में नैसर्गिक कानून का यह सूत्र नहीं था। मीसा में जिला प्रशासन द्वारा व्यक्ति को उठाकर जेल भेज दिया जाता था। न्यायालय में उसका मुकदमा नहीं चलता था। ऐसा कानून दुनिया के किसी भी सभ्य देश में नहीं है। लेकिन भारत में पुलिस राज था। पुलिस अनावश्यक रूप से पोटी थी। हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंग भंग किये गये। संविधान संशोधनों की झड़ी लग गई। 53 अनुच्छेद एक साथ बदले गये। सातवीं अनुसूची बदली गई। प्रेस का मुहूर कुचल दिया गया था। सब तरफ उत्पीड़न व सरकार प्रायोजित हिंसा का चीत्कार था। मौलिक अधिकार भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्राण हैं। वे स्थापित सरकार के अत्याचारों से रक्षा करने के उपकरण हैं। राज व्यवस्था की निरंकुशता से संरक्षण देने के लिए मौलिक अधिकार अधिनियमित किये गये थे। श्रीमती ईंदिरा गांधी मौलिक अधिकारों में भी काट छाट कर रही थीं। संविधान (भाग 4) में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के बहाने बनाई गई विधियों को न्यायालिक निर्वचन से अलग रख दिया गया था। सरकारी अत्याचारों से देश उबल रहा था। मुझे मीसा बंदी के रूप में उत्पीड़न का अनुभव है। उस समय लागू डिफेन्स ऑफ ईंडिया रूल (डीआईआर) का भी अनुभव है।



हृदयनारायण दीक्षित

लोकतंत्र पर जबरदस्त आघात

सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में देश पर तानाशाही पूर्वक लगाया गया आपातकाल है। जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही समाप्त कर दिया था। इसे एक प्रकार से देश की आजादी को छीनने का दुस्साहसिक प्रयास भी माना जा सकता है। क्योंकि इंदिरा शासन द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल में सरकार के विरोध में आवाज उठाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। यहां तक कि सरकार ने विषय की राजनीति करने वालों के साथ ही उन समाजसेवियों और राष्ट्रीय विचार के प्रति समर्पित उन संस्थाओं के व्यक्तियों को जेल में ठूंस दिया था, जो सरकार की कमियों के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे थे। सरकार के इस कदम को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अपनी सरकार के खिलाफ उठाने वाली हर उस आवाज को दबाने का प्रयास किया, जो लोकतांत्रिक रूप से भी सही थी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस शासन का यही चरित्र रहा है कि उनके खिलाफ उठाने वाली आवाज को किसी भी प्रकार से शांत किया जाय। आज भी कांग्रेस ठीक इसी पद्धति से काम करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी जाती रही है। इसे कांग्रेस का स्वभाव ही माना जा सकता है कि उसने देश को मजबूत करने वाली आवाज को मुखर नहीं होने दिया। इसके विपरीत देश के विरोध में उठाने वाली आवाज को बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की आजादी कहकर समर्थन किया। सीधे शब्दों में निरुपित किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अपने विरोध में कही गई कोई बात जरा भी पसंद नहीं है। इसी कारण नेशनल हेरेल्ड में जब जाँच की बात आती है तो कांग्रेस के नेता एकजुट होकर ऐसा प्रदर्शन करते हैं, जैसे वहीं सही हैं और बाकी सभी गलत। कांग्रेस पार्टी ने

एक नहीं कई बार अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने काम किया है, लेकिन जो कांग्रेस गाहे बगाहे अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करती रही है, उसने ही 25 और 26 जून 1975 की रात को आपातकाल लगाने के बाद अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह गला घोंट दिया था। अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार कुठराघात किया जाता है, इस तथ्य को जानने के लिए कांग्रेस के नेताओं को आपातकाल के काले अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। आपातकाल के नाम पर कांग्रेस ने अंग्रेजों से भी भयंकर यातनाएं देते हुए देश भक्तों पर कहर बरपाया। जिसके स्मरण मात्र से दिल में सिरहन दौड़ जाती है। जिन लोगों ने इस काली रात का साक्षात्कार किया, उनके अनुभव सुनने मात्र से ही लगता है कि इन्होंने आपातकाल को किस कदर भोगा होगा। आपातकाल लगाने के पाठे के करारों पर दृष्टिपात किया जाए तो यही तथ्य सामने आते हैं कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूरी तरह से तानाशाह शासक की भूमिका में दिखाई दीं। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा बताते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, यह प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही था। वह निर्णय क्या था? इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को पराजित किया था, लेकिन चुनाव परिणाम अनेकों के चार साल बाद राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर छह साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे और त्रीमंती गांधी के चिर प्रतिद्वंद्वी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर

दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तथ सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। न्यायालय ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और देश में आपातकाल घोषित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ ही गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इन्दिरा गांधी ने न्यायालय के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी का यह कदम न्यायालय के आदेश का अपमान करने वाला ही था। आपातकाल के नाम पर केवल उर्ध्वी लोगों को जेल में जबरदस्ती बंद किया था, जो सरकार के विरोधी थे। देश भर में इंदिरा शासन के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। आपातकाल में शासन, प्रशासन ने लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हर उस व्यक्ति को प्रताड़ना दी, जो लोकतांत्रिक तरीके सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे थे। विपक्षी राजनेताओं ने देश में केन्द्र सरकार के विरोध में ऐसा बातावरण बनाया कि इंदिरा गांधी को अपना सिंहासन हिलाता हुआ दिखाई दिया। जॉर्ज फर्नार्डीज को लोहे की जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी गईं। देश के जितने भी बड़े नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेले राजनीतिक पाठशाला बन गईं। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा, उनका यही कहना था कि ऐसा दृश्य तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं दिखा।

■ सुरेश हिंदुस्थानी

विदेशी मीडिया का इस संबंध में खूब हारा लिया जाता है। बीबीसी गजरात दंगे के 20 साल बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जनरल की पत्रकार सबरीना सिद्धीकी को भारत में हो रहे विकास या मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछने की बजाय सिर्फ अल्पसंख्यकों की चिंता सताती है।

10 of 10

अमेरिका आगमन से पहले कुछ भारत विरोधी अमेरिकी सांसदों से एक पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखवाया और उनसे मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। भारत विरोधी कुछ अमेरिकी सांसदों ने मोदी के स्वागत समारोह और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के संबोधन का बहिष्कार भी किया। यह लोग मोदी की अमेरिका यात्रा के दैरान ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट भी करते रहे ताकि मोदी विरोधी अभियान को गति मिलती रहे। इसके अलावा, एक ओर उमर खालिद को रिहा करने की मांग संबंधी पोस्टर अमेरिका में लहराये गये तो दूसरी ओर खालिस्तान समर्थकों ने भी भारत विरोधी नारे लगाये। इस

था कि वह भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका यात्रा का वीजा प्रदान करे। यही नहीं, 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जब ओबामा भारत आये तो अपने एक संबोधन में मोदी सरकार को मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उपदेश देना नहीं भूले थे।

अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो मोदी से उनकी गहरी दोस्ती ओबामा को कर्तई पसंद नहीं आती थी। इसलिए 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ओबामा ने जो बाइडन के लिए जमकर प्रचार भी किया। जो बाइडन को अमेरिका स्थित मुस्लिम संगठनों का पूरा समर्थन दिलाने में भी ओबामा की बड़ी भूमिका रही थी। ओबामा को उम्मीद थी कि बाइडन के कार्यकाल में

विदेशी मीडिया का इस संबंध में खूब सहारा लिया जाता है। बीबीसी गुजरात दंगों के 20 साल बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जनरल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को भारत में हो रहे विकास या मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रश्न पूछने की बजाय सिर्फ अल्पसंख्यकों की चिंता सताती है।

बीच, सबके सुर से सुर
मिलाते हुए बराक ओबामा
ने सीएनएन को साक्षात्कार देकर माहौल गमाने का प्रयास
कर अपना भी योगदान दे दिया। देखा जाये तो बराक हुसैन
ओबामा के मन में मोदी विरोधी भावना आज से नहीं बल्कि
शुरू से ही है। ओबामा को 2014 में यह कहाँ नहीं भाया
था कि आम चुनावों में नंदें मोदी के नेतृत्व में भाजपा की
इतनी प्रचंड विजय हुई कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से सीधे
मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गये। मोदी के प्रधानमंत्री बनने
के बाद ओबामा प्रशासन इस बात के लिए मजबूर हो गया

मोदी विरोधी अभियान आगे
बढ़ेगा लेकिन बाइडन तो
मोदी से दोस्ती के मामले में ट्रंप से भी आगे बढ़ गये। ओबामा
देखते रहे गये कि उनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बाइडन
कैसे मोदी से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और वैश्विक
नेता के रूप में मोदी को मान्यता दे रहे हैं। इसलिए जब मोदी
को अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा का निमंत्रण मिला
तो ओबामा की खींच स्वाभाविक थी। जहां तक ओबामा की
ओर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा बार-बार उठाये
जाने और भारत को नसीहत देने की बात है तो इस बारे में

कहा जा सकता है कि ओबामा को पहले यह सीख अपने देश को देनी चाहिए। देखा जाये तो बराक हुसैन ओबामा बहुत बड़े ढोंगी हैं। उनके कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो पायेंगे कि अपने पूर्ववर्ती जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मुकाबले अपने कार्यकाल में ओबामा ने दस गुना ज्यादा एअर स्ट्राइक करवायीं। बुश के कार्यकाल में कुल 57 हवाई हमले हुए थे जबकि ओबामा के कार्यकाल में 563 हवाई हमले हुए। जो हवाई हमले हुए वह सभी मुस्लिम देशों पर हुए जिनमें पाकिस्तान, सेमालिया, यमन, अफगानिस्तान और सीरिया आदि शामिल हैं। ओबामा के आदेश पर हुए हवाई हमलों में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं मारे गये बल्कि हजारों की संख्या में आम नागरिक भी हताहत हुए। इसके अलावा, जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा नस्लवाद या रंग के आधार पर भेदभाव की घटनाएं सापें आती हैं वह दूसरों को सीख देने से पहले यदि अपने अंतर्मन में जाके तो बेहतर रहेगा। सीएनएन पर ओबामा का पूरा साक्षात्कार पढ़ेंगे तो यह भी पता चलेगा कि उन्होंने बुझे मन से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका में अगवानी की थी। अपने साक्षात्कार में ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष कई बार यह मजबूरी होती है कि हम जिन्हे पसंद नहीं करते उनका भी स्वयंत करना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है। बहराहाल, ओबामा के साक्षात्कार को पढ़ कर लगता है कि उन्हें अब भी यह भ्रम है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और विश्व के मामलों में उनकी कोई भूमिका है। देखा जाये तो ओबामा अपने कार्यकाल में दुनिया को तमाम समस्याएं ही देकर गये हैं जिनकी भरपाई अमेरिका सहित अन्य देश कर रहे हैं। मानवधिकार प्रेमी का मुख्यालय लगाये इस शाखा के कार्यकाल में गलत नीतियों की वजह से जितने आम नागरिक मारे गये उसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।

■ नीरज कुमार दुबे

■ अजय कुमार शर्मा

